

## 606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 नवम्बर 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 606वीं बैठक दिनांक 14/11/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री चंद्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव । ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No 8769/2021 M/s. Wonder Cement Ltd, Shri P. Patidar, Director, 17, Old Fatehpura, Seva Mandir, Dist. Udaipur, Raj. - 313004 Prior Environment Clearance for Expansion in Limestone Quarry in an area of 44.293 ha. (Limestone - 200000 Tonne per annum, Sub Grade / Screen Reject - 15055 Tonne per annum) (Khasra No. 1, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4/1, 4/4/2, 4/4/3, 4/4/4, 4/4/5, 4/5, 30, 37, 40/1, 41/1, 41/2, 42/1, 44, 45, 46, 47, 48), Village - Kosdana, Tehsil - Gandhwani, Dist. Dhar (MP). Env. Consl.: Shri S.S. Bist M/s. Udaipur Min-Tech Pvt. Ltd., Udaipur.**

This is case of Limestone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4/1, 4/4/2, 4/4/3, 4/4/4, 4/4/5, 4/5, 30, 37, 40/1, 41/1, 41/2, 42/1, 44, 45, 46, 47, 48), Village - Kosdana, Tehsil - Gandhwani, Dist. Dhar (MP) 44.293 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 528<sup>th</sup> SEAC dated 23/11/2022 wherein ToR was recommended. PP has submitted the EIA report forwarded by SEIAA on-line and the same was scheduled in the agenda. As per the decision taken during TOR presentation, site visit was conducted by a sub-committee of SEAC and inspection report was discussed in the 541<sup>st</sup> SEAC meeting dated 20.01. 2022.

## 606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 नवम्बर 2022

आज दिनांक 14/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील देशमुख (ऑनलाईन), जनरल मैनेजर, पर्यावरण और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री एस.एस. बिष्ट, मेसर्स उदयपुर मिनटेक प्रा.लि., उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आर.ओ.एम. 2,15,055 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष है जिसमें से 2,00,000 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष लाईम स्टोन है तथा 15,055 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष सब ग्रेड रिजेक्ट है। इस परियोजना के अंतर्गत एक 250 टी.पी.एच. का केशर विथ वायब्रेटिंग स्क्रीन भी लगाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि यह खदान शासकीय एवं निजी भूमि पर आक्शन के माध्यम से आवंटित एक लाईम स्टोन खदान है, जिसका कुल रकबा 44.293 हे. है, जिसमें से 28.642 हे. शासकीय भूमि तथा 15.651 हे. निजी भूमि है। निजी भूमि का अभिग्रहण किया जाना बाकी है तथा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन कार्य अभी शासकीय भूमि 28.642 हे. पर किया जायेगा तथा धीरे-धीरे निजी भूमि का अभिग्रहण खनन कार्य शुरू होने के पश्चात् करा लिया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि खनन के प्रारम्भ में कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नहीं है अपितु परियोजना अवधि में 40 पेड़ों की पुर्नस्थापना की जाना प्रस्तावित की गई है।

आवंटित खनन क्षेत्र के दक्षिण-पूर्वी दिशा में 200 मीटर पर जलाशय/एनीकट है जिसके सुरक्षा हेतु चेक डेम, गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक का प्रस्ताव दिया गया है। जन सुनवाई में स्कूल एवं हास्पिटल का निर्माण, पाईप लाईन की सिफ्टिंग, गांव एवं परिवहन मार्ग पर वृक्षारोपण, सड़क का निर्माण, जन-स्वास्थ्य के कार्य इत्यादि कार्य हेतु सुझाव प्राप्त हुए थे जिसको ई.एम.पी. एवं सी.आर. में शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण पश्चात् के समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

1. समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना वित्तीय प्रस्ताव सहित, जिसमें खदान के अतिरिक्त अन्य जगहों जैसे : स्थानीय स्कूल, गाँव इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपण तथा धार वन मण्डलाधिकारी से शासन के निर्देशानुसार सी.ई.आर. के तहत 10.00 हे. की भूमि पर सघन वृक्षारोपण हेतु योजना।
2. भूमि अपरदन रोकने के लिए उत्तर-पूर्व दिशा में बैरियर जोन के समीप अतिरिक्त चेकडेम (नक्शों में दर्शाते हुए) का प्रस्ताव।
3. स्थल निरीक्षण दौरान दिए गए निर्देशानुसार उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित नाले में स्टोन पिचिंग का कार्य किया गया है, अतः कितने क्षेत्र में पिचिंग का कार्य किया जाना है, का विवरण।
4. लीज क्षेत्र में से निकल रही पाईप लाईन का डायवर्जन प्रस्तावित किया गया है, जिस हेतु ग्राम पंचायत की सहमति प्राप्त की जाये।
5. आवंटित खनन क्षेत्र में 15.651 हे. जो निजी भूमि है वह किन-किन आदिवासियों की है उसे खसरा नंबर के हिसाब से तालिका व खसरा मेप पर (भूमि के माप) से दर्शाया जाये तथा निजी भूमि खनन कार्य हेतु उपयोग में लाई जानी है, अतः उन सभी से किये गये एग्रीमेंट की फोटो प्रति प्रस्तुत की जाये।
6. आवंटित खनन क्षेत्र में 15.651 हे. आदिवासियों की निजी भूमि को खनन कार्य में उपयोग करने पर भूमि स्वामी आदिवासी को क्षतिपूर्ति (Compensation) किस नियम से कितना-कितना दिया जायेगा तथा खनन कार्य पश्चात् किस प्रकार इस निजी भूमि को कृषि कार्य हेतु पुर्नस्थापित (Restore) किया जायेगा, वित्तीय प्रस्ताव ई.एम.पी. में शामिल कर प्रस्तुत करें।

**606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 14 नवम्बर 2022**

7. आवंटित खनन क्षेत्र में 15.651 हे. निजी भूमि का वर्तमान कृषि उत्पाद तथा उसका मूल्य क्या है की जानकारी प्रमाणिक स्रोत से प्राप्त कर प्रस्तुत की जाये ।
8. चूँकि खनन कार्य हेतु शासकीय भूमि का उपयोग किया जायेगा, अतः समतुल्य भूमि पर चारागाह विकास की योजना प्रस्तुत करें । उक्त विषय में वन विभाग से भी चारागाह भूमि विकास हेतु चर्चा कर वन भूमि पर चारागाह योजना प्रस्तुत की जा सकती है ।
9. टॉर बिंदु क्रमांक-37 अनुसार वाटर होल के संरक्षण हेतु स्थानीय उपयोगकर्ताओं से चर्चा कर समुचित योजना प्रस्तुत करें ।
10. आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्वी भाग में स्थित मन नाले के एच.एफ.एल. से खदान की दूरी (एच.एफ.एल. को नक्शों पर दर्शाते हुए) तथा मन नाले से मिलने वाले सरफेस ड्रेन्स के संरक्षण हेतु उनके किनारों पर स्थानीय घास प्रजाति के वृक्षारोपण की योजना ।

**2. Case No 8025/2020 M/s MOIL Limited, Shri Kishore Chandraker, Senior DGM, MOIL Bhavan, 1A, Katol Road, Dist. Nagpur, Mah. – 440013. Prior Environment Clearance for Expansion of Manganere Ore Mine in an area of 69.581 ha. (10,000 to 1,20,000 Tonne per annum) Khasra No. Lugma : 61, 58/1, 58/2, 58/3, 60/1, 60/2, 60,3, 62/02, 62/9, 56/1, 56/2, P.O.5, P.O.64, 65/1 to 65/6, 66P.O., 68, 49/1 to 49/8 P.O.57, 42/1, 42/2, 67/1 to 67/6, 43/1 to 43/4, 45/1 P.O.45/2, P.P.46, 92/1, 92/2, 93, 94, 95, P.O.98/1 to 98/9 Ukwa : P.O.5, 6/2, 7, 9, 10, 12 Tehsil - Paraswada, Dist. Balaghat, (MP).**

This is case of Expansion of LUGMA-UKWA MANGANESE ORE MINING PROJECT". The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site Village - Lugma - Ukwa, Tehsil - Paraswada, Dist. Balaghat, (MP) 69.581 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 473<sup>rd</sup> SEAC dated 07/01/2021 wherein ToR was recommended. PP has submitted the EIA report forwarded by SEIAA on-line and the same was scheduled in the agenda.

The EIA was presented by Env. Consultant Shri G. k. Mishra from M/s. GMEC International Pvt ltd. Jaipur and their representatives on behalf of PP Shri C.B. Atulkar , Technical Director (Mine), MOIL, Nagpur.

In the begning of presentation, it was observed by the committee that accreditation of the Environmental consultancy firm certificate M/s. GMEC International Pvt Ltd. Jaipur has expired on 07.11.2022 for which consultant submitted that they have applied for its renewal and same is yet not renewed. Committee deliberated that at the time of presentation the environmental consultancy firm does not have valid accreditation at the time of appearing

**606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 14 नवम्बर 2022**

before the SEAC and thus can not make presentation in accordance with the MoEF&CC OM dated 03.03.2016 which reads as follows:

*“.....shall be allwed to prepare the EIA & EMP of a project in that sector and category and to appear before the concern Expert Appraisal Committee (EAC) or the stated Expert Appraisal Committee.”*

Committee after deliberations decided that this case shall be further considered after producing valid accreditation certificate from NABET/QCI through on line Portal PARIVESH and instructed consultant to submit the same within 30 days time for further consideration of the case.

**3. Case No 8686/2021 Smt. Seema Agrawal W/o Shri Madan Agrawal, Village – Kasai, Tehsil - Lakhnadon, Dist. Seoni, MP – 480886 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.85 ha. (19998 cum per annum) (Khasra No. 291), Village - Kasai, Tehsil - Lakhnadon , Dist. Seoni (MP) Amaltas Enviro Industrial Consultants LPP, Gurugram. Haryana.**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 291), Village - Kasai, Tehsil - Lakhnadon , Dist. Seoni (MP) 1.85 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 521वीं दिनांक 14/10/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

In the begning of presentation, it was observed by the committee that accreditation of the Environmental consultancy firm certificate M/s. GMEC International Pvt Ltd. Jaipur has expired on 07.11.2022 for which consultant submitted that they have applied for its renewal and same is yet not renewed. Committee deliberated that at the time of presentation the environmental consultancy firm does not have valid accreditation at the time of appearing before the SEAC and thus can not make presentation in accordance with the MoEF&CC OM dated 03.03.2016 which reads as follows:

*“.....shall be allwed to prepare the EIA & EMP of a project in that sector and category and to appear before the concern Expert Appraisal Committee (EAC) or the stated Expert Appraisal Committee.”*

**606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 14 नवम्बर 2022**

Committee after deliberations decided that this case shall be further considered after producing valid accreditation certificate from NABET/QCI through on line Portal PARIVESH and instructed consultant to submit the same within 30 days time for further consideration of the case.

**4. Case No 9403/2022 Shri Ashok Ahirwar, Owner, Hanuman Mandir sa Samna, Tilli Ward, Sagar, Tehsil- Sagar, Dist. Sagar, MP - 470001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (10260 Cum per annum) (Khasra No. 93), Village - Majhguwa Ahir, Tehsil - Sagar, Dist. Sagar (MP)**

This is case of for Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 93), Village - Majhguwa Ahir, Tehsil - Sagar, Dist. Sagar (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक अहिरवार, (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1131 दिनांक 08/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 5.00 हे. होने के कारण प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश-देशांश का अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश-देशांश से मिलान नहीं हो रहा है। अतः समिति ने निर्णय लिया कि इस प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी से स्थिति स्पष्ट कराते हुए प्रस्तावित खदान के वास्तविक अक्षांश-देशांश संबंधी जानकारी 15 दिवस में प्राप्त करें।

**5. Case No 9400/2022 M/s Maa Rewa Stone Crusher, Partner, Shri Satya Prakash Chandela, Village - Gokulthana, Dist. Mandla, MP - 481661, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.90 ha. (11876 Cum per annum) (Khasra No. 358, 366), Village - Lakhmadungariya, Tehsil - Nainpur, Dist. Mandla (MP)**

This is case of for Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 358, 366), Village - Lakhmadungariya, Tehsil - Nainpur, Dist. Mandla (MP) 3.90 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

## 606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 नवम्बर 2022

आज दिनांक 14/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री सत्य प्रकाश चंदेल, (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 265 दिनांक 03/03/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्व दिशा में 125 मीटर पर पक्का रोड़, 05 मीटर पर कच्चा रोड़ है। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कच्चे रोड़ से 05 मीटर का सेटबैक प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न है। साथ ही पूर्व दिशा में 05 मीटर पर प्राकृतिक नाला है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इसके संरक्षण हेतु 45 मीटर का सेटबैक के साथ गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित है। खदान क्षेत्र में स्थित कोई भी काटा जाना प्रस्तावित नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 59 के सरल क्रमांक-2 पर इस खदान का विवरण दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 11,876 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.81 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 04.66 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम लखमापुरडुंगरिया में ग्राम पंचायत के परामर्श से हैंडपंप लगवाया जावेगा।	70,000/-
योग	70,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4680 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
-----	---	---------------------	---------------------

**606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 14 नवम्बर 2022**

1	बैरियर जोन में	आवला, नीम, खमेर, चिरोल, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल एवं अन्य स्थानीय प्रजीतिया	700
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, करंज, सप्तपर्णी, चिरोल, बरगद, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजीतिया ट्री-गार्ड के साथ	250
3	ग्राम लखमापुरडुंगरिया के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	नीम, कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, आम, कटहल, आवला करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजीतिया	50
4	ग्राम गोकलथाना के शासकिय विद्यालय परिसर में उपलब्ध क्षेत्र पर	कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, सप्तपर्णी, नीम, पीपल, चिरोल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजीतिया	100
5	खदान में प्रस्तावित गैर खनन क्षेत्र में	खमेर, चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल एवं अन्य स्थानीय प्रजीतिया	600
6	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आवला, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, अनार, इमली, निम्बू, कटहल एवं अन्य स्थानीय प्रजीतिया	2980
		<b>कुल वृक्षारोपण</b>	<b>4680</b>

**6. Case No 9401/2022 Shri Sanjay Baghel, Lessee Owner, 1180, University Road, South Civil Line, Dist. Jabalpur, MP - 482002, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.50 ha. (1,94,356 Cum per annum) (Khasra No. 444), Village - Amiliha, Tehsil - Gurh, Dist. Rewa (MP)**

This is case of for Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 444(P)), Village - Amiliha, Tehsil - Gurh, Dist. Rewa (MP) 3.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री संजय बघेल, (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोएडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2768 दिनांक 29/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में

## 606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 नवम्बर 2022

01 अस्थाई अनुज्ञा खनिज पत्थर गिट्टी हेतु 04.900 हे. स्वीकृत की गई थी, जिसकी अवधि 08/05/19 से 31/03/22 तक थी। इस प्रकार प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में 255 मीटर पर पक्का रोड़, पश्चिम दिशा में 70 मीटर पर प्राकृतिक नाला तथा पश्चिम दिशा में 200-250 मीटर दूर आईसोलेटिड हटमेंट्स है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्राकृतिक नाला के संरक्षण हेतु गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टेक प्रस्तावित किये गये हैं। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के समय परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल इमेज तथा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट ऐरिया मेप के अनुसार वन क्षेत्र लगभग लगभग 80 से 90 मीटर की दूरी पर आ रहा है जबकि प्रकरण के साथ अपलोडिड एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 1425 दिनांक 13/09/2022 वन क्षेत्र 265 मीटर दूर है। उपरोक्त स्थिति में समिति की अनुशंसा है कि चूंकि परिवेश पर अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र वन क्षेत्र से लगभग 80 से 90 मीटर की दूरी पर आ रहा है अतः संबंधित वन मण्डलाधिकारी से इस स्थिति स्पष्ट करने बावत् पत्र लिखा जाये।

7. **Case No 7466/2020 M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd, Authorized Signatory, Shri Virendra Singh Jadon, E-7/M-708, Arera Colony, Distt. Bhopal, MP - 462016 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 6.0 ha. (63000 cum per annum) (Khasra No. 263, 350), Village - Mudgudi, Tehsil - Manpur, Dist. Umariya (MP). Env. Consultant M/s. Greencindia Consulting Private Limited Ghaziabad (U.P.)**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 263, 350), Village - Mudgudi, Tehsil - Manpur, Dist. Umariya (MP) 6.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 452वीं दिनांक 27/08/2020 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 553वीं दिनांक 22/02/2022 में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई थी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल की बैठक क्र०. 749 वीं दिनांक 23/09/2022 के द्वारा पर्यायवर्णीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत प्रकरण को रिलिस्ट करते हुये सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 553वीं दिनांक 22/02/2022 में समिति द्वारा चाही गई जानकारी ऑनलाइन ADS के माध्यम से जमा न करते हुये ऑफलाईन जमा की गई है। अतः प्रकरण को SEAC के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराये।



## 606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 नवम्बर 2022

- अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को सेक की 599 वीं बैठक दिनांक 08/10/2022 में चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के समक्ष चर्चा हेतु रखा गया। समिति ने पाया कि सेक की 553वीं बैठक दिनांक 22/02/2022 में वांछित जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान उसी दिन हार्डकापी में प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर प्रकरण पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित सिया को प्रेषित किया गया था जिसके संदर्भ में सिया से प्राप्त निर्देशानुसार (बैठक क्र०. 749 वीं दिनांक 23/09/2022) यह जानकारी ऑनलाईन ADS के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जाना है। अतः परियोजना प्रस्तावक सिया से प्राप्त निर्देशानुसार उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन (ए.डी.एस.) के माध्यम से प्रस्तुत करें।

उक्त निर्देशानुसार परिवेश पोर्टल पर दिनांक 14/10/22 को ए.डी.एस. जारी किया गया, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित जानकारियों को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 31/10/22 को अपलोड कर दिया गया है।

प्रकरण आज दिनांक 14/11/22 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें समिति ने पाया चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के समक्ष चर्चा हेतु रखा गया तथा इस बैठक में उमरिया जिले की रेत खनिज की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षण उपरांत पाया गया कि उपरोक्त प्रकरण डी.एस.आर. के पेज क्र०. -97 में दर्ज है। चर्चा के दौरान समिति ने निर्धारित किया गया कि चूंकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माइनेवल मिनरल पोर्टेंशियल 1,08,000 घनमीटर है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित फार्म-2 में 63,000 घन मीटर रेत की मात्रा दर्शायी गई है। अतः समिति को 63,000 घन मीटर रेत की मात्रा पुनः अनुशंसित की जा सकती है।

समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि चूंकि प्रकरण सेक की पूर्व की 553वीं दिनांक 22/02/2022 में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है, अतः पूर्व की अनुशंसानुसार से सहमत होते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किया जाय।

**8. Case No 7467/2020 M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd, Authorized Signatory, Shri Virendra Singh Jadon, E-7/M-708, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP - 462016 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 6.981 ha. (69810 cum per annum) (Khasra No. 05), Village – Khairbhar-2, Tehsil - Chandiya, Dist. Umariya (MP). Env. Consultant M/s. Greencindia Consulting Private Limited Ghaziabad (U.P.)**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 05), Village - Khairbhar-2, Tehsil - Chandiya, Dist. Umariya (MP) 6.981 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

## 606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 नवम्बर 2022

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 452वीं दिनांक 27/08/2020 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 553वीं दिनांक 22/02/2022 में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल की बैठक क्र०. 749 वीं दिनांक 23/09/2022 के द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत प्रकरण को रिलिस्ट करते हुये सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 553वीं दिनांक 22/02/2022 में समिति द्वारा चाही गई जानकारी ऑनलाईन ADS के माध्यम से जमा न करते हुये ऑफलाईन जमा की गई है। अतः प्रकरण को SEAC के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराये।
- अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को सेक की 599 वीं बैठक दिनांक 08/10/2022 में चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के समक्ष चर्चा हेतु रखा गया । समिति ने पाया कि सेक की 553वीं बैठक दिनांक 22/02/2022 में वांछित जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान उसी दिन हार्डकापी में प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर प्रकरण पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित सिया को प्रेषित किया गया था जिसके संदर्भ में सिया से प्राप्त निर्देशानुसार (बैठक क्र०. 749 वीं दिनांक 23/09/2022) यह जानकारी ऑनलाईन ADS के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जाना है । अतः परियोजना प्रस्तावक सिया से प्राप्त निर्देशानुसार उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन (ए.डी.एस.) के माध्यम से प्रस्तुत करें।

उक्त निर्देशानुसार परिवेश पोर्टल पर दिनांक 14/10/22 को ए.डी.एस. जारी किया गया, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित जानकारियों को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 31/10/22 को अपलोड कर दिया गया है ।

प्रकरण आज दिनांक 14/11/22 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें समिति ने पाया चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के समक्ष चर्चा हेतु रखा गया तथा इस बैठक में उमरिया जिले की रेत खनिज की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षण उपरांत पाया गया कि उपरोक्त प्रकरण डी.एस.आर. के पेज क्र०. -98 में दर्ज है। चर्चा के दौरान समिति ने निर्धारित किया गया कि चूंकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माइनेवल मिनरल पोर्टेंशियल 1,25,658 घनमीटर है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित फार्म-2 में 69,810 घन मीटर रेत की

## 606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 नवम्बर 2022

मात्रा दर्शायी गई है। अतः समिति को 69,810 घन मीटर रेत की मात्रा पुनः अनुशंसित की जा सकती है।

समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि चूँकि प्रकरण सेक की पूर्व की 553वीं दिनांक 22/02/2022 में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है, अतः पूर्व की अनुशंसानुसार से सहमत होते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किया जाय।

9. **Case No 7441/2020 M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd, Authorized Signatory, Shri Virendra Singh Jadon, E-7/M-708, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP – 462016, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 5.260 ha. (78900 cum per annum) (Khasra No. 01), Village – Koylari, Tehsil – Chandia, Dist. Umariya (MP). Env. Consultant M/s. Greencindia Consulting Private Limited Ghaziabad (U.P.)**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01), Village – Koylari, Tehsil – Chandia, Dist. Umariya (MP) 5.260 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 452वीं दिनांक 27/08/2020 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 553वीं दिनांक 22/02/2022 में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई थी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल की बैठक क्र०. 749 वीं दिनांक 23/09/2022 के द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत प्रकरण को रिलिस्ट करते हुये सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 553वीं दिनांक 22/02/2022 में समिति द्वारा चाही गई जानकारी ऑनलाईन ADS के माध्यम से जमा न करते हुये ऑफलाईन जमा की गई है। अतः प्रकरण को SEAC के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराये।
- अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को सेक की 599 वीं बैठक दिनांक 08/10/2022 में चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के समक्ष चर्चा हेतु रखा गया। समिति ने पाया कि सेक की 553वीं बैठक दिनांक 22/02/2022 में वांछित जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान उसी दिन हार्डकापी में प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर प्रकरण पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित सिया को प्रेषित किया गया था जिसके संदर्भ में सिया से प्राप्त निर्देशानुसार (बैठक क्र०. 749 वीं दिनांक 23/09/2022) यह जानकारी ऑनलाईन ADS के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक

## 606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 नवम्बर 2022

से प्राप्त की जाना है। अतः परियोजना प्रस्तावक सिया से प्राप्त निर्देशानुसार उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन (ए.डी.एस.) के माध्यम से प्रस्तुत करें।

उक्त निर्देशानुसार परिवेश पोर्टल पर दिनांक 14/10/22 को ए.डी.एस. जारी किया गया, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित जानकारियों को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 31/10/22 को अपलोड कर दिया गया है।

प्रकरण आज दिनांक 14/11/22 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें समिति ने पाया चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के समक्ष चर्चा हेतु रखा गया तथा इस बैठक में उमरिया जिले की रेत खनिज की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षण उपरांत पाया गया कि उपरोक्त प्रकरण डी.एस.आर. के पेज क्र०. -98 में दर्ज है। चर्चा के दौरान समिति ने निर्धारित किया गया कि चूंकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माइनेवल मिनरल पोर्टेंशियल 94,680 घनमीटर है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित फार्म-2 में 78,900 घन मीटर रेत की मात्रा दर्शायी गई है। अतः समिति को 78,900 घन मीटर रेत की मात्रा पुनः अनुशंसित की जा सकती है।

समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि चूंकि प्रकरण सेक की पूर्व की 553वीं दिनांक 22/02/2022 में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है, अतः पूर्व की 553वीं दिनांक 22/02/2022 अनुशंसानुसार से सहमत होते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किया जाय।

**10. Case No 7442/2020 M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd, Authorized Signatory, Shri Virendra Singh Jadon, E-7/M-708, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP – 462016 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 20.0 ha. (3,60,000 cum per annum) (Khasra No. 591/1228), Village – Govarde, Tehsil – Manpur, Dist. Umariya (MP)**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 591, 1228), Village – Govarde, Tehsil – Manpur, Dist. Umariya (MP) 20.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 452वीं दिनांक 27/08/2020 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 553वीं दिनांक 22/02/2022 में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई थी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल की बैठक क्र०. 749 वीं दिनांक 23/09/2022 के द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत प्रकरण को रिलिस्ट करते हुये सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 553वीं दिनांक 22/02/2022 में समिति द्वारा चाही गई जानकारी ऑनलाईन ADS के माध्यम से जमा न

## 606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 नवम्बर 2022

करते हुये ऑफलाईन जमा की गई है। अतः प्रकरण को SEAC के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराये।

- अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को सेक की 599 वीं बैठक दिनांक 08/10/2022 में चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के समक्ष चर्चा हेतु रखा गया। समिति ने पाया कि सेक की 553वीं बैठक दिनांक 22/02/2022 में वांछित जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान उसी दिन हार्डकापी में प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर प्रकरण पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित सिया को प्रेषित किया गया था जिसके संदर्भ में सिया से प्राप्त निर्देशानुसार (बैठक क्र०. 749 वीं दिनांक 23/09/2022) यह जानकारी ऑनलाईन ADS के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जाना है। अतः परियोजना प्रस्तावक सिया से प्राप्त निर्देशानुसार उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन (ए.डी.एस.) के माध्यम से प्रस्तुत करें।

उक्त निर्देशानुसार परिवेश पोर्टल पर दिनांक 14/10/22 को ए.डी.एस. जारी किया गया, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित जानकारी को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 31/10/22 को अपलोड कर दिया गया है।

प्रकरण आज दिनांक 14/11/22 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें समिति ने पाया चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के समक्ष चर्चा हेतु रखा गया तथा इस बैठक में उमरिया जिले की रेत खनिज की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षण उपरांत पाया गया कि उपरोक्त प्रकरण डी.एस.आर. के पेज क्र०. -97 में दर्ज है। चर्चा के दौरान समिति ने निर्धारित किया गया कि चूंकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माइनेवल मिनरल पोटेन्शियल 3,60,000 घनमीटर है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित फार्म-2 में 3,90,000 घन मीटर रेत की मात्रा दर्शायी गई है। जो कि माइनेवल मिनरल पोटेन्शियल से अधिक मात्रा है। अतः समिति ने उपलब्ध माइनेवल मिनरल पोटेन्शियल की मात्रा अर्थात् 3,60,000 घन मीटर रेत की मात्रा ही अनुशंसित करने का निर्णय लिया है।

समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि चूंकि प्रकरण सेक की पूर्व की 553वीं दिनांक 22/02/2022 में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है, अतः की पूर्व अनुशंसा में संशोधन करते हुए समिति ने अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माइनेवल मिनरल पोटेन्शियल 3,60,000 घनमीटर उपलब्ध माइनेवल मिनरल पोटेन्शियल की मात्रा अर्थात् 3,60,000 घन मीटर रेत की मात्रा ही पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसित है तथा अन्य शर्तें सेक की 553वीं दिनांक 22/02/2022 अनुसार ही रहेंगी।

**606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 14 नवम्बर 2022**

**11. Case No 7465/2020 M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd, Authorized Signatory, Shri Virendra Singh Jadon, E-7/M-708, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP – 462016 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 5.744 ha. (57440 cum per annum) (Khasra No. 29/1, 29/2), Village – Kodar, Tehsil – Manpur, Dist. Umariya (MP). Env. Consultant M/s. Greencindia Consulting Private Limited Ghaziabad (U.P.).**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 29/1, 29/2), Village – Kodar, Tehsil – Manpur, Dist. Umariya (MP) 5.744 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 452वीं दिनांक 27/08/2020 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 553वीं दिनांक 22/02/2022 में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल की बैठक क्र0. 749 वीं दिनांक 23/09/2022 के द्वारा पर्यायवर्णीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत प्रकरण को रिलिस्ट करते हुये सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 553वीं दिनांक 22/02/2022 में समिति द्वारा चाही गई जानकारी ऑनलाईन ADS के माध्यम से जमा न करते हुये ऑफलाईन जमा की गई है। अतः प्रकरण को SEAC के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराये।
- अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को सेक की 599 वीं बैठक दिनांक 08/10/2022 में चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के समक्ष चर्चा हेतु रखा गया । समिति ने पाया कि सेक की 553वीं बैठक दिनांक 22/02/2022 में वांछित जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान उसी दिन हार्डकापी में प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर प्रकरण पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित सिया को प्रेषित किया गया था जिसके संदर्भ में सिया से प्राप्त निर्देशानुसार (बैठक क्र0. 749 वीं दिनांक 23/09/2022) यह जानकारी ऑनलाईन ADS के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जाना है । अतः परियोजना प्रस्तावक सिया से प्राप्त निर्देशानुसार उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन (ए.डी.एस.) के माध्यम से प्रस्तुत करें।

उक्त निर्देशानुसार परिवेश पोर्टल पर दिनांक 14/10/22 को ए.डी.एस. जारी किया गया, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित जानकारियों को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 31/10/22 को अपलोड कर दिया गया है ।

## 606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 नवम्बर 2022

प्रकरण आज दिनांक 14/11/22 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें समिति ने पाया चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के समक्ष चर्चा हेतु रखा गया तथा इस बैठक में उमरिया जिले की रेत खनिज की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षण उपरांत पाया गया कि उपरोक्त प्रकरण डी.एस.आर. के पेज क्र०. -98 में दर्ज है। चर्चा के दौरान समिति ने निर्धारित किया गया कि चूँकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माइनेवल मिनरल पोटेन्शियल 1,03,392 घनमीटर है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित फार्म-2 में 57,440 घन मीटर रेत की मात्रा दर्शायी गई है। अतः समिति को 57,440 घन मीटर रेत की मात्रा पुनः अनुशंसित की जा सकती है।

समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि चूँकि प्रकरण सेक की पूर्व की 553वीं दिनांक 22/02/2022 में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है, अतः पूर्व की 553वीं दिनांक 22/02/2022 अनुशंसानुसार से सहमत होते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किया जाय।

**12. Case No 7447/2020 M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd, Authorized Signatory, Shri Virendra Singh Jadon, E-7/M-708, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP – 462016 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 9.50 ha. (95000 cum per annum) (Khasra No. 566/1226), Village – Govarde, Tehsil – Manpur, Dist. Umariya (MP)**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 566/1226), Village – Govarde, Tehsil – Manpur, Dist. Umariya (MP) 5.744 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 452वीं दिनांक 27/08/2020 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 553वीं दिनांक 22/02/2022 में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई थी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल की बैठक क्र०. 749 वीं दिनांक 23/09/2022 के द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत प्रकरण को रिलिस्ट करते हुये सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 553वीं दिनांक 22/02/2022 में समिति द्वारा चाही गई जानकारी ऑनलाईन ADS के माध्यम से जमा न करते हुये ऑफलाईन जमा की गई है। अतः प्रकरण को SEAC के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराये।

## 606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 नवम्बर 2022

- अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को सेक की 599 वीं बैठक दिनांक 08/10/2022 में चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के समक्ष चर्चा हेतु रखा गया। समिति ने पाया कि सेक की 553वीं बैठक दिनांक 22/02/2022 में वांछित जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान उसी दिन हार्डकापी में प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर प्रकरण पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित सिया को प्रेषित किया गया था जिसके संदर्भ में सिया से प्राप्त निर्देशानुसार (बैठक क्र०. 749 वीं दिनांक 23/09/2022) यह जानकारी ऑनलाईन ADS के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जाना है। अतः परियोजना प्रस्तावक सिया से प्राप्त निर्देशानुसार उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन (ए.डी.एस.) के माध्यम से प्रस्तुत करें।

उक्त निर्देशानुसार परिवेश पोर्टल पर दिनांक 14/10/22 को ए.डी.एस. जारी किया गया, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित जानकारियों को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 31/10/22 को अपलोड कर दिया गया है।

प्रकरण आज दिनांक 14/11/22 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें समिति ने पाया चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के समक्ष चर्चा हेतु रखा गया तथा इस बैठक में उमरिया जिले की रेत खनिज की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षण उपरांत पाया गया कि उपरोक्त प्रकरण डी.एस.आर. के पेज क्र०. -98 में दर्ज है। चर्चा के दौरान समिति ने निर्धारित किया गया कि चूंकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माइनेवल मिनरल पोर्टेंशियल 1,71,000 घनमीटर है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित फार्म-2 में 95,000 घन मीटर रेत की मात्रा दर्शायी गई है। अतः समिति को 95,000 घन मीटर रेत की मात्रा पुनः अनुशंसित की जा सकती है।

समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि चूंकि प्रकरण सेक की पूर्व की 553वीं दिनांक 22/02/2022 में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है, अतः पूर्व की 553वीं दिनांक 22/02/2022 अनुशंसानुसार से सहमत होते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किया जाय।

(चंद्र मोहन ठाकुर)  
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)  
अध्यक्ष



## 606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 नवम्बर 2022

**Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:**

### **Annexure- 'A'**

#### **Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:**

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

## 606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 नवम्बर 2022

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

## 606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 नवम्बर 2022

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

37. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

**नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

**नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

**नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

**नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

**नोट 7 :-** बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

### **Annexure- 'B'**

#### **Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\***

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

## 606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 नवम्बर 2022

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be  $1/4^{\text{th}}$  or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - f. Lease owner's Name, Contact details etc.

## 606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 नवम्बर 2022

- g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - i. Minable Potential of sand mine.
  - j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - k. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
- i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
  - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
  - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
  - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
  - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
  - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
  - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
  - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
  - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

## 606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 नवम्बर 2022

- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई ।		

### नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

### Annexure- 'C'

#### Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries\*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain

## 606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 नवम्बर 2022

- a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
  15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
  16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
  17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
  18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
  19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
  20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
  21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
  22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
  23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
  24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
  25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
  26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    - l. Lease owner's Name, Contact details etc.
    - m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    - n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    - o. Minalable Potential of sand mine.
    - p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    - q. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
  27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

## 606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 नवम्बर 2022

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Anganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

**नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

**नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

**नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

**नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माइनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साइड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

**नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।



## 606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 नवम्बर 2022

- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

### **Annexure- 'D'**

#### **General conditions applicable for the granting of TOR**

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

## 606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 नवम्बर 2022

24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2<sup>nd</sup> August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
  - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
  - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
  - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
  - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
  - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
  - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

## 606वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 नवम्बर 2022

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
  - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
  - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई -
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

**नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

**FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained